

**Title:** Regarding counting of SC&ST persons for the Census Report in Delhi.

**श्री सालखन मुर्मू (म्यूरभंज) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश में देश के विभिन्न प्रदेशों से आये हुए जो आदिवासी हैं, एस.सी.एस.टी. हैं, उनको दिल्ली प्रदेश की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। एस.टी. के रूप में उनको जो सुविधायें मिलनी चाहिए, दिल्ली प्रदेश में ये सुविधायें बिल्कुल नहीं मिलती। अब दूसरा इश्यु होने वाला है और जो मुझे जानकारी मिली है कि जो जनगणना होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है और जो इन्सुमिरेटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग के दौरान बताया जा रहा है कि जो एस.सी.एस.टी. के कॉलम्स बनते हैं और दिल्ली में बसने वाले जो आदिवासी हैं, एस.टी. हैं, उनको एस.टी. कॉलम में न रखा जाये, एनी-अदर में रखा जाये ताकि दिल्ली में जो जनगणना होगी, उसमें आदिवासियों की संख्या न दिखायी जाये, यह गंभीर मामला है। एस.एस.एस.टी. के अधिकार का मामला है, संवैधानिक अधिकार का मामला है। दिल्ली में विभिन्न राज्यों से आये हुए आदिवासी भाइयों को कोई सुविधा नहीं मिलती है और यदि अभी ऐसे इश्यु के तहत आदिवासियों की संख्या नगण्य दिखायी जाएगी तो यह आपत्तिजनक बात है।